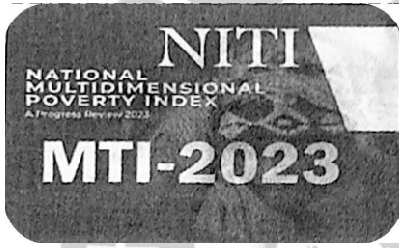


सामाजिक परिदृश्य

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2023

- 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 (National Multidimensional Poverty Index % Progress Review 2023) रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार, भारत में बड़ी संख्या में लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं।



मुख्य बिंदु

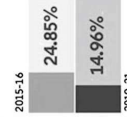
- आधार :** यह रिपोर्ट नवीनतम 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5' (NFTS) 2019-21 के आधार पर तैयार की गई है।
 - इसमें NHFS-4 (2015-16) और NHFS-5 (2019-21) हैं के मध्य बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति का विश्लेषण किया गया है।
- दूसरा संस्करण:** यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक सर्वाधिक गिरावट बिहार राज्य में हुई है। इसके पश्चात मध्य MPI का दूसरा संस्करण है। MPI का पहला संस्करण वर्ष 2021 में जारी किया गया था।
- आयाम एवं संकेतक :** यह सूचकांक एक साथ तीन आयामों में होने वाले अभावों को मापता है; थे तीन आयाम हैं-
 - स्वास्थ्य एवं पोषण (Health and Nutrition), शिक्षा (Education) और जीवन स्तर (Standard of Living)
 - उपर्युक्त तीन आयामों को पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास, संपत्ति और बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों द्वारा दर्शाया जाता है।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- बहुआयामी गरीबी में कमी:** भारत में बहुआयामी गरीबी का सामना करने वाले लोगों की संख्या में व्यापक कमी हुई है और वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 की अवधि के मध्य लगभग 13.5 करोड़ लोग इससे बाहर हुए हैं।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) प्रगति रिपोर्ट 2023

कुल गरीबी के अनुपात में भारी गिरावट



135 मिलियन लोग (13.5 करोड़)



2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी से गरीबी बाहर निकले



भारत 2030 से पहले ही एसडीजी लक्ष्य 1.2 को (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा कम करना) प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

भारत में सभी 12 संकेतकों में सुधार हुआ है जिससे पता चलता है कि सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव तृणमूल स्तर पर तेजी से हो रहा है।

- इसी प्रकार बहुआयामी गरीबी के तहत आने वाली जनसंख्या को प्रतिशत अंकों में लगभग 9.89% की गिरावट देखने को मिली है। वर्ष 2015-16 में इसके तहत लगभग 24.85% जनसंख्या शामिल थी जो घटकर वर्ष 2019-21 में 14.96% हो गई है।

- ग्रामीण शहरी विभाजन:** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों का तुलना में गरीबी में तीव्र गिरावट देखने को मिली है। ग्रामीण गरीबी पर वर्ष 2015-16 की 32.59% को वर्ष 2019-21 में 19.28% हो गई। इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर 8.6594 से घटकर 5.27% हो गई।

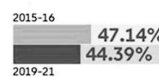
ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी के प्रतिशत में तीव्र गिरावट



शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी



गरीबी की तीव्रता, जो बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों के बीच असंतुलन का मापनी है, में सुधार



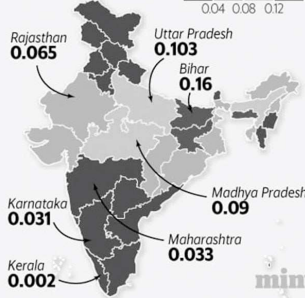
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में एमपीआई गरीबी की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है।



पोषण में सुधार, स्कूली शिक्षा के वर्षों, स्वच्छता और खाना पकाने के ईंधन ने एमपीआई मूल्य को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- राज्य स्तरीय प्रगति:** बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त लोगों की संख्या के संदर्भ में सबसे बड़ी गिरावट उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। यहाँ लगभग 3.43 करोड़ (343 मिलियन) लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए।

Multidimensional poverty index (scale: 0-1)
(the lower, the better)



Biggest drops in share of multidimensionally poor population (percentage points)

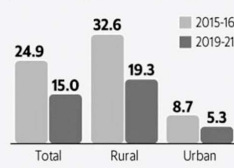


A multidimensionally poor person is one who is at least 33.3% deprived overall (this is based on 12 indicators, all of which has a different weightage). Headcount ratio is the share of multidimensionally poor persons in population. Intensity refers to the average extent of deprivation among such persons (hence always >33.3%). The MPI value is headcount multiplied by intensity. Source: Niti Aayog

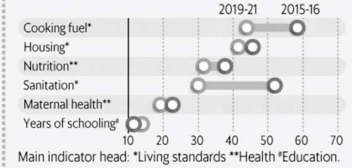
CHANGING FORTUNES

Around 24.9% of Indians were assessed as multidimensionally poor in 2015-16, but that share came down to 15% in 2019-21.

Share of multidimensionally poor persons in population (in %)



Biggest areas of 'deprivation' (figures denote % share of population 'deprived' in each indicator)



Main indicator head: *Living standards **Health *Education.

- बहुआयामी गरीबी मूल्य (MPI Value) के आधार पर सर्वाधिक गिरावट बिहार राज्य में हुई है। इसके पश्चात् मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है।

- **SDG लक्ष्य:** वर्ष 2015-16 एवं 2019-21 के दौरान, MPI मूल्य 0.117 से गिरकर 0.066 हो गया है तथा गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई।

- इससे प्रदर्शित होता है कि भारत वर्ष 2030 की निर्धारित समय-सीमा से पहले SDG (सतत विकास लक्ष्य) लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा करना) हासिल करने की राह पर है।

- **संकेतकों में सुधार:** बहुआयामी गरीबी को मापने के लिये उपयोग किये जाने वाले सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। उदाहरण-स्वच्छता में 23.8% तथा खाना पकाने के ईंधन में 14.6% का सुधार दर्ज किया गया है।



महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पर रिपोर्ट

17-20 जुलाई 2023 के मध्य किगाली (रवांडा) में 'विमेन दिलोवर कांफ्रेंस (Women Deliver Conference WD2023) का आयोजन किया गया।



इस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र महिला (UN WOMEN DELIVER 2023 CONFERENCE Women) एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा श्रमानता का मार्ग महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर जुड़वां सूचकांक' (The Paths To Equal Twin Indices On Women's Empowerment And Gender Equality) नामक रिपोर्ट जारी की गई।

मुख्य बिंदु

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के दो संगठनों संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UN) Development Programme) द्वारा तैयार की गई है।
- संबंधित आंकड़ों को 114 देशों से संकलित किया गया है तथा 'महिला सशक्तिकरण सूचकांक' (Women's Empowerment Index : WEI) एवं 'वैश्विक लिंग समानता सूचकांक' (Global Gender Equality Index : GGPI) के जुड़वां सूचकांक का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है।
 - महिला सशक्तिकरण सूचकांक के तहत विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन में विकल्पों के चुनाव एवं अवसरों का लाभ उठाने की उनकी शक्ति तथा स्वतंत्रता का मापन किया जाता है।
 - वैश्विक लिंग समानता सूचकांक, मानव विकास के मुख्य आयाम में पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति का आकलन करता है तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता में अंतर का पता लगाता है।
- यून वूमेन** : यह संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। वर्ष 2010 में स्थापित इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क (अमेरिका) में है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) पर संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह देशों को गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास एवं मानव विकास करने में मदद करता है। इसकी पना वर्ष 1965 में हुई इस न्यूयॉर्क (अमेरिका) में है।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

रिपोर्ट में अध्ययन किए गए 114 देशों में से किसी भी देश ने 'पूर्ण महिला सशक्तिकरण' या 'पूर्ण लैंगिक समानता' हासिल नहीं की है।

- 114 में से 85 देशों में महिलाओं के प्रभाव का स्तर कम या मध्यम (Low or Medium) है और लैंगिक समानता की उपलब्धि भी कम या मध्यम (Low or Medium) है।
- विश्व भर में केवल 1% महिलाएं ही उन देशों में रहती हैं, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता दोनों के उच्च स्तर हासिल किए हैं।
- हालांकि विश्व की 90% से अधिक महिलाएं ऐसे देशों में रहती हैं, जहां महिलाओं के प्रभाव स्तर तथा लैंगिक समानता दोनों निम्न या मध्यम (Low or Medium) स्तर पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, नेतृत्व और निर्णय लेने वाले पद अभी भी मुख्य रूप से पुरुषों के पास हैं और महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- भारतीय परिदृश्य**: भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का स्तर 'निम्न' पाया गया, हालांकि मानव विकास के मामले में भारत को 'मध्यम' श्रेणी वाले देश के रूप में जाना जाता है।

व्यापक राजनीतिक उपायों की आवश्यकता

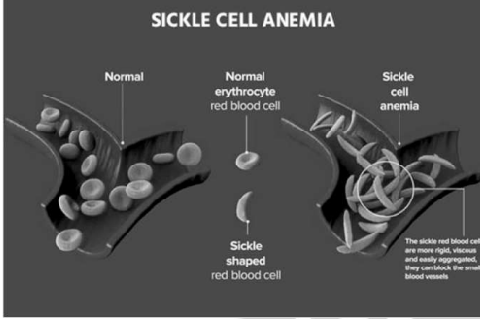
- स्वास्थ्य नीति (Health Policy)**: चीन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुंच पर ध्यान देने के साथ सभी महिलाओं के लिए लंबे और स्वस्थ जीवन का समर्थन एवं प्रचार की आवश्यकता है।
- शिक्षा में समानता (Equity in Education)**: डिजिटल युग में महिलाओं और लड़कियों को बनाने के लिए, विशेष रूप से STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) जैसे क्षेत्रों में शल और शिव गुणवत्ता अतिरिक्त को संबोधित करना चाहिए।
- कार्य-जीवन संतुलन और सहायक परिवार (Work - Life Balance and Supporting Families)**: किफायती और गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल माता-पिता को और लचीली कार्य व्यवस्था सहित कार्य-जीवन संतुलन नीतियों और सेवाओं निवेश पर बल दिया जाना चाहिए।
- महिलाओं की समान भागीदारी**: सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता हासिल करने और महिलाओं को पीछे रखने वाले भेदभावपूर्ण कानूनों और नियमों की खत्म करने के लिए लक्ष्य एवं कार्य योजनाएं निर्धारित करना की मांग है।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा से बचना**: ऐसे व्यापक उपायों को लागू किया जाना चाहिए, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम करें। इस दिशा में, सामाजिक मानदंडों में बदलाव तथा भेदभावपूर्ण कानूनों एवं मोतियों को समाप्त करने को भी आवश्यकता है।



सिकल सेल एनीमिया

सन्दर्भ -

- केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गयी कि सरकार 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन मोड में कार्य करेगी।



सिकल सेल एनीमिया

- सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक विकार है, जो लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है।
- लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग उसमे पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, जो शरीर में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाता है।
- सिकल सेल एनीमिया ऐसा रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी टूट जाती हैं जिसके कारण एनीमिया तथा अन्य जटिलताएं जैसे कि वेसो- ओक्लुसिव क्राइसिस, फेफड़ों में संक्रमण, एनीमिया, गुर्दे और यकृत की विफलता, स्ट्रोक आदि के कारण रूग्णता और मृत्यु की सम्भावना होती है।
- प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो आकार में गोल, नर्म और लचीली होती हैं।
- यह लाल रक्त कोशिकाएं जब स्वयं के आकार से भी सूक्ष्म धमनियों में से प्रवाह करती हैं तब वह अंडाकार आकार की हो जाती है।
- सूक्ष्म धमनियों से बाहर निकलने के पश्चात कोशिकाओं के लचीलेपन के कारण वे पुनः अपना मूल स्वरूप ले लेती हैं।
- सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं परिवर्तित हो कर अर्धगोलाकार तथा सख्त/कड़क हो जाती हैं जिसे सिकल सेल कहा जाता है।
- इससे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है या कई बार अवरुद्ध हो जाता है।
- इसके अलावा, सिकल कोशिकाएं जल्दी मर जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है जो शरीर को ऑक्सीजन से वंचित कर देती हैं।

- लाल रक्त कोशिकाओं का यह विकार जीन की विकृति के कारण होता है।
- सिकल सेल के रोगी दो प्रकार के होते हैं , सिकल सेल वाहक (लक्षण रहित/मंद लक्षण) एवं सिकल सेल रोगी (गंभीर लक्षण)।
- प्रथम प्रकार अर्थात सिकल सेल वाहक व्यक्ति रोग के वाहक के रूप में काम करते हैं अर्थात उनमें सिकल सेल के रोग के लक्षण स्थायी न होकर कभी - कभी दिखाई देते हैं, ये व्यक्ति अपने बच्चों को वंशानुगत यह रोग देते हैं।
- दूसरे प्रकार के सिकल रोगी वह व्यक्ति होते हैं जिनमें रोग के लक्षण स्थायी रूप से रहते हैं, जिससे उनके शरीर का विकास रुक जाता है, ये निश्चित रूप से अपने बच्चों को यह रोग देते हैं।

उपचार

- सिकल सेल रोग को आजीवन बीमारी कहा जाता है तथा रक्त और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण को इस रोग के लिए एकमात्र कुशल इलाज कहा जाता है।
- जीन थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को भी इसके संभावित इलाज के रूप में देखा जाता है।
- भारत में सिकल सेल एनीमिया
- भारत, सिकल सेल एनीमिया से दूसरा सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है।
- भारत में, लगभग 18 मिलियन लोगों में सिकल सेल के लक्षण हैं, तथा 1.4 मिलियन लोग, सिकल सेल रोग से प्रभावित हैं।
- सिकल सेल एनीमिया, भारत में जनजातीय आबादी में व्यापक रूप से फैला हुआ है, जनजातीय आबादी में प्रत्येक 86 जन्मों में से लगभग 1 सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित होता है।
- भारत के कुछ राज्यों में एससीडी का प्रचलन काफी अधिक है। इसमें शामिल है -
- छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, ओडिशा, केरल और राजस्थान।
- इन राज्यों को सामूहिक रूप से सिकल सेल बेल्ट कहा जाता है।
- विभिन्न राज्यों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा इस बीमारी के बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए सिकल सेल रोग सहायता कॉर्नर लॉन्च किया है।



वैश्विक सुरक्षा पहल (GSI)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में, चीन द्वारा ग्लोबल सिक्वोरिटी इनिशिएटिव (जीएसआई) की स्थापना की गई है।

प्रमुख बिन्दु

- चीन ने इस पहल का उद्देश्य एशिया में स्थिरता और सुरक्षा को बहाल करना बताया है।
- हालांकि कुछ विदेशी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल वास्तविक प्रयास के बजाय अमेरिकी नेतृत्व के लिए एक प्रति-उत्तर के रूप में अधिक प्रतीत होती है।

वैश्विक सुरक्षा पहल क्या है?

- इस पहल को चीन के विदेश मामलों के मंत्री किन गेंग ने बीजिंग में लैंटिंग फोरम में पेश किया था।
- यह पहल पांच स्तंभों पर आधारित है;
 - आपसी सम्मान
 - खुलापन और समावेश
 - बहुपक्षवाद
 - पारस्परिक लाभ
 - एक समग्र दृष्टिकोण
- समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, इसलिए चीन द्वारा ऐसे सिद्धांतों को बढ़ावा देना विश्व में वैकल्पिक नेता के रूप में उभरने का प्रयास है।

चीन का मौजूदा दृष्टिकोण

- आपसी सम्मान-** संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर देता है। यह आपसी विश्वास और सम्मान पर भी ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि, यह सुझाव दिया जाता है कि चीन अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों में इस सिद्धांत की अवहेलना करता है। उदाहरण के लिए,

- यह नई दिल्ली के साथ विश्वास-निर्माण के उपायों की एकतरफा अवहेलना करता है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भी कमजोर करता है।
- यह दक्षिण चीन सागर में एक मुखर नीति का अनुसरण करता है।
- इसके अलावा, यह UNCLOS को खारिज करता है।
- चीन पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता को सिरे से खारिज करता है। यह क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने की कोशिश करता है जिससे खुलेपन और समावेश के सिद्धांत की अवहेलना होती है।
- हालांकि चीन विभिन्न बहुपक्षीय संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन वह उन्हें असममित शक्ति संबंधों के चश्मे से देखता है। उदाहरण के लिए,
- चीन आसियान सदस्यों को सामूहिक रूप से अपने दावे के खिलाफ कार्य करने के लिए विवश करता है। इस प्रकार बीजिंग द्वारा बहुपक्षीय सुरक्षा के सिद्धांत का भी पालन नहीं किया जाता है।
- चौथा सिद्धांत सहयोग और पारस्परिक लाभ पर प्रकाश डालता है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को एक बहुत ही आवश्यक सहकारी ढांचे के रूप में पेश करता है।
- हालांकि, वास्तविकता यह है कि बीआरआई के तहत अस्थिर परियोजनाओं ने कम या गैर-मौजूदा क्रेडिट रेटिंग वाले देशों पर अधिक वित्तीय बोझ पैदा किया है।
- अंतिम सिद्धांत पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों के लिए समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता है। अमेरिका और भारत जैसे देशों के साथ चीन का जुड़ाव उसके शक्ति हित को दर्शाता है।

निष्कर्ष

- यह सुझाव दिया गया है कि चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल (जीएसआई) दुनिया में बढ़ती असुरक्षा के लिए एक न्यायसंगत, टिकाऊ और पारदर्शी समाधान होने से बहुत दूर है।
- यह केवल कथाओं (narrative) के माध्यम से अमेरिकी नेतृत्व का मुकाबला करने का एक प्रयास है।

प्रोजेक्ट री-हैब (RE – HAB)

सन्दर्भ

- हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष द्वारा प्रोजेक्ट RE-HAB (मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों के मानव पर होने वाले हमलों को कम करना) के तहत कर्नाटक में प्रशिक्षित लाभार्थियों को जीवंत मधुमक्खी पालन उपकरण और 200 मधुमक्खी-बक्से वितरित किए गए।

प्रोजेक्ट RE-HAB

- प्रोजेक्ट RE-HAB राष्ट्रीय शहद मिशन के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की एक पहल है।
- इसका उद्देश्य मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों द्वारा मानव पर होने वाले हमलों को कम करना है।

- RE – HAB परियोजना के तहत हाथियों के मानव आवासों में उनके प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खियों के बक्सों को स्थापित करके 'मधुमक्खी-बाड़ें' बनाई जाती हैं।
- इन बक्सों को एक तार से जोड़ा जाता है, जिससे हाथियों द्वारा वहां से गुजरने का प्रयास करने पर एक खिंचाव के कारण मधुमक्खियां हाथियों के बीच में आ जाती हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं।
- यह जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मानव-पशु टकराव को कम करने का एक कुशल तरीका है।
- यह वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया गया है कि हाथी मधुमक्खियों के झुण्ड से डरते हैं, जो उनके सूंड और आंखों के संवेदनशील अंदरूनी हिस्से को काट सकती हैं।

- ☛ मधुमक्खियों की सामूहिक भनभनाहट हाथियों को परेशान करती है, जो उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देती है।
- ☛ RE-HAB के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
- ☛ इसके अलावा हाथियों को खेतों में घुसने से रोकने के लिए किसानों को हाथी गलियारों में लगाने के लिए मधुमक्खी बक्से भी दिए जाते हैं।

प्रोजेक्ट RE – HAB के लाभ

- ☛ भारत में हाथियों के हमले से प्रति वर्ष लगभग 500 लोगों की मौत हो जाती है।
- ☛ यह देश भर में बाघों के हमले से होने वाली मौतों से लगभग 10 गुना अधिक है।
- ☛ 2015 से 2020 तक हाथियों के हमले में करीब 2500 लोगों की जान जा चुकी है, इसमें से करीब 170 लोगों की मौत अकेले कर्नाटक में हुई है।
- ☛ पिछले 5 वर्षों में लगभग 500 हाथी भी मनुष्यों द्वारा प्रतिशोध में मारे गए हैं।
- ☛ प्रोजेक्ट RE-HAB हाथियों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मानव-हाथी संघर्ष को कम करता है।
- ☛ यह बाड़ लगाना या खाइयाँ खोदने जैसे पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत लागत प्रभावी उपाय है।
- ☛ यह हाथियों को वन क्षेत्रों के पास के गाँवों में प्रवेश करने से रोकने का एक बेहतर और मानवीय तरीका भी है।
- ☛ इस पहल से शहद का उत्पादन भी बढ़ेगा तथा किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, तथा इससे फसल को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा।

- ☛ प्रोजेक्ट RE-HAB का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हाथियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उन्हें दूर भगाता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

- ☛ यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- ☛ केवीआईसी का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास की योजना बनाना, बढ़ावा देना, सुविधा देना, संगठित करना और सहायता करना है।
- ☛ यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत कार्य करता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्य

- ☛ रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य।
- ☛ बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य।
- ☛ गरीबों के बीच आत्मनिर्भरता पैदा करने और एक मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करने का व्यापक उद्देश्य।

शहद मिशन कार्यक्रम

- ☛ यह मिशन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा 2017-18 में लॉन्च किया गया था।
- ☛ यह मधुमक्खी पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण भारत में किसानों, आदिवासियों और बेरोजगार युवाओं के बीच आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लागू किया जा रहा है।
- ☛ कार्यक्रम के तहत, लाभार्थियों को मधुमक्खी बक्सों, मधुमक्खी कालोनियाँ, टूल किट और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।



Most Trusted Learning Platform



KHAN SIR



क्वाड साइबर चौलेंज

चर्चा में क्यों

- हाल ही में क्वाड समूह द्वारा अपने सदस्य देशों में साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए एक सार्वजनिक अभियान, श्क्वाड साइबर चौलेंज शुरू किया गया।

क्वाड साइबर चौलेंज

- क्वाड साइबर चौलेंज, निगमों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों, छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों तक सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा जानकारी और प्रशिक्षण तथा संसाधन प्रदान करेगा
- क्वाड साइबर चौलेंज साइबर सुरक्षा जागरूकता और कार्रवाई को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था तथा उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक अधिक सुरक्षित और लचीले साइबर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्वाड देशों के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।
- क्वाड देश यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, कि ऑनलाइन और स्मार्ट उपकरणों का उपयोग करते हुए सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक संसाधनों तक सभी की पहुंच हो।
- भारत में क्वाड साइबर चौलेंज का समन्वय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ राष्ट्रीय साइबर समन्वयक कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

क्वाड



- यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है।
- यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है।
- क्वाड का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन तथा शांति व सुरक्षा पर बल प्रदान करना है।
- इसकी उत्पत्ति 2004 के तदर्थ सुनामी कोर ग्रुप से हुई थी, जिसने इस क्षेत्र के कई देशों को तबाह करने वाली सुनामी के बाद आपदा राहत कार्यों में सहयोग किया था।
- क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
- वर्ष 2017 में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने क्वाड का गठन किया।
- क्वाड नेताओं की पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक 2021 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी।

